



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 वैशाख 1932 (श0)  
(सं0 पटना 320) पटना, वृहस्पतिवार, 13 मई 2010

संख्या-3ए-3-भत्ता-01/2009 - 5015-वि.

वित्त विभाग

संकल्प

12 मई 2010

विषय:- अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों को मंहगाई भत्ता की दरों में दिनांक 1 जनवरी 2010 से संशोधन के फलस्वरूप दिनांक 1 जनवरी 2010 के प्रभाव से मंहगाई भत्ता की स्वीकृति ।

वित्त विभाग के संकल्प सं0 12084 दिनांक 18 दिसम्बर 2009 द्वारा अपुनरीक्षित वेतन प्राप्त करने वाले राज्य कर्मियों को दिनांक 1 जुलाई 2009 के प्रभाव से 73 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता की स्वीकृति दी गयी थी ।

2. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय झापांक-1(3)/2008-EII(B) दिनांक 31 मार्च 2010 द्वारा अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे केन्द्रीय कर्मियों (यानि जिनका वेतन पुनरीक्षण 1 जनवरी 2006 से नहीं हुआ है) को दिनांक 1 जनवरी 2010 से 73 प्रतिशत से बढ़ाकर 87 प्रतिशत मंहगाई भत्ता के रूप में स्वीकृत किया गया है ।

3. राज्य सरकार नीतिगत रूप से केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ता को राज्य कर्मियों के लिए स्वीकृत करने का निर्णय ले चुकी है । तदनुसार केन्द्र सरकार द्वारा मंहगाई भत्ता की दरों में संशोधन के पश्चात् राज्य कर्मियों को उक्त दर पर मंहगाई भत्ता अनुमान्य किया जाता है ।

4. अतः केन्द्रीय कर्मियों के सदृश्य अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे राज्य कर्मियों को दिनांक 1 जनवरी 2010 के प्रभाव से मंहगाई भत्ता की दरों में निम्नवत् संशोधन किया जाता है-

(क) दिनांक 1 जनवरी 2006 के पूर्व दिनांक 1 जनवरी 1996 के प्रभाव से लागू पुनरीक्षित वेतनमान (सम्प्रति अपुनरीक्षित) में वेतन प्राप्त करने वाले कर्मियों तथा जिनको दिनांक 1 जनवरी 2005

के प्रभाव से मूल वेतन के 50 प्रतिशत राशि के समतुल्य मंहगाई भत्ता की राशि को मंहगाई वेतन के रूप में लाभ दिया जा चुका है, को दिनांक 1 जनवरी 2010 के प्रभाव से मंहगाई भत्ता की दर 73 प्रतिशत से बढ़ाकर 87 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है ।

(ख) मंहगाई भत्ता की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा ।

(ग) मंहगाई भत्ते का भुगतान मूल वेतन एवं मंहगाई वेतन के सम्मिलित योग के आधार पर परिगणित कर किया जाएगा किन्तु विशेष वेतन/वैयक्तिक वेतन पर मंहगाई भत्ता अनुमान्य नहीं होगा । मंहगाई भत्ता की गणना में 50 पैसे से उपर की राशि पूर्ण रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा ।

5. उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान में उक्त मंहगाई भत्ता का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद की स्वीकृति से देय होगा ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

रबीन्द्र पवारं,

सचिव (संसाधन) ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 320-571+500-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>